

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

मेरा यह कथन है कि, महामारी ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया है। कमी के संकेतों के बावजूद, कई देशों में दैनिक संक्रमणों की रिकॉर्ड संख्या और परिणामी रोकथाम के उपाय आर्थिक गतिविधियों की गति को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों में, यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान जारी है और प्रतिबंधित कार्यबल की भागीदारी श्रम बाजारों को सख्त करती है। कई देशों में मुद्रास्फीति बहु-दशक के उच्च स्तर पर है, विभिन्न मौद्रिक नीति इरादों और कार्यों द्वारा विकसित समष्टि आर्थिक वातावरण को अत्यधिक अनिश्चित बना दिया जा रहा है। वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव दृष्टिकोण में द्विपक्षीयता की परतें जोड़ रहे हैं।

कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरियंट द्वारा संचालित एक अत्यधिक संक्रामक तीसरी लहर के बावजूद, भारत शेष दुनिया से बहाली का एक अलग पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष-दर-वर्ष सबसे तेज गति से बढ़ने की ओर अग्रसर है। यह बहाली बड़े पैमाने पर टीकाकरण और निरंतर वित्तीय और मौद्रिक समर्थन द्वारा समर्थित है। एक बार फिर, हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा सराहनीय रूप से कर्तव्य की ओर अग्रसर हुए हैं।

जैसे-जैसे हम महामारी की बार-बार लहरों से मूल्यवान अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे-वैसे हमारी प्रतिक्रियाएँ भी सूक्ष्म और अंशशोधित होती जा रही हैं। जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि है; और आजीविका की रक्षा प्राथमिकताओं के पदानुक्रम में बढ़ रही है। कमजोर लोगों, वेतन पाने वालों और सबसे अधिक पीड़ित लोगों की आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, लक्षित रोकथाम रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है और सार्वभौमिक टीकाकरण और बूस्टर खुराक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को हमारे कार्यस्थलों और हमारे दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के बढ़ते

उपयोग से पूरक के रूप में लिया जा रहा है। ये प्रयास आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान की सीमा को सीमित करने के लिए किया जा रहा है।

मौद्रिक नीति समिति के विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 8, 9 और 10 फरवरी 2022 को हुई और वर्तमान समष्टिआर्थिक स्थिति और संभावनाओं के आकलन के आधार पर, इसने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। एमपीसी ने 5 से 1 के बहुमत से निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे चलकर मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, और टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और उसे बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाया रखा जाए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है। रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

एमपीसी ने अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन वेरियंट से आर्थिक गतिविधियों के लिए संभावित नकारात्मक जोखिमों को चिह्नित किया। आश्वस्त रूप से, लक्षण अपेक्षाकृत हल्के बने हुए हैं और संक्रमण की गति जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी ही तेज़ी से कम हो रही है। हालांकि, आर्थिक गतिविधियों की गति में कुछ कमी आई है, जो उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है, जैसे कि विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए क्रय प्रबंधकों के सूचकांक, तैयार स्टील की खपत और ट्रैक्टरों, दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री। संपर्क-गहन सेवाओं की मांग अभी भी कम है। आगे बढ़ते हुए, रबी की उछाल भरी संभावनाओं, मजबूत निर्यात मांग, निभावकारी मौद्रिक और तरलता की स्थिति, ऋण उठाव में सुधार, और केंद्रीय बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर निरंतर दबाव से बहाली की गति को तेज करने के लिए सकारात्मक आवेग उत्पन्न हो रहे हैं।

एमपीसी ने यह भी नोट किया कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अपनी पिछली बैठक के बाद से अधिक बढ़ी है, लेकिन मोटे तौर पर प्रत्याशित सीमा के साथ। दिसंबर में मुद्रास्फीति में वृद्धि पूरी तरह से कीमतों में महीने-दर-महीने गिरावट के बावजूद प्रतिकूल

* गवर्नर का वक्तव्य - 10 फरवरी 2022

आधार प्रभावों के कारण हुई थी। अनाज के बड़े बफर स्टॉक और प्रभावी आपूर्ति पक्ष उपाय, खाद्य मुद्रास्फीति के लिए शुभ संकेत हैं। मुख्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है, लेकिन मांग-प्रेरित दबाव अभी भी कम है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नए सिरे से उछाल पर कड़ी निगरानी की जरूरत है।

समग्र रूप से, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यू4:2021-22 में सहिष्णुता बैंड के भीतर चरम पर होने की उम्मीद है और फिर एच2:2022-23 में लक्ष्य के करीब मध्यम, तथा मौद्रिक नीति को समायोजित रहने के लिए जगह प्रदान करता है। इसी समय, उत्पादन अपने पूर्व-महामारी स्तर से मुश्किल से ऊपर है, जबकि निजी खपत अभी भी पिछड़ रही है। वैश्विक हेडविंड जोर दे रहे हैं। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति और विकास की संभावनाएं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति संभावना में सुधार, ओमिक्रोन और वैश्विक स्पिलओवर से संबंधित अनिश्चितताओं द्वारा प्रदान की गई सुविधा को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी का विचार था कि निरंतर नीति समर्थन एक टिकाऊ और व्यापक-आधारित बहाली की आवश्यकता है।

घरेलू वृद्धि

भारत में, 2021-22 के लिए 9.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि इसे 2019-20 में जीडीपी के स्तर से मामूली रूप से ऊपर ले जाती है। निजी खपत, घरेलू मांग का मुख्य आधार, अपने पूर्व-महामारी स्तर को पीछे छोड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में लगातार वृद्धि, वैश्विक वित्तीय बाजारों की अस्थिरता में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से संभावना के लिए जोखिम बढ़ सकता है।

भविष्य में, पूंजीगत व्यय और निर्यात पर सरकार के जोर से उत्पादक क्षमता में वृद्धि और कुल मांग को मजबूत करने की उम्मीद है। इससे निजी निवेश में भी भीड़ होगी। आरबीआई की नीतिगत कार्रवाइयों से उत्पन्न अनुकूल वित्तीय स्थितियां निवेश गतिविधि को गति प्रदान करेंगी। आरबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि क्षमता उपयोग बढ़ रहा है, और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास पर दृष्टिकोण आशावादी क्षेत्र में बना हुआ है, जिससे निवेश के साथ-साथ खपत की मांग का समर्थन प्राप्त होगा।

। सर्दियों की फसल की बुआई की अच्छी प्रगति से कृषि की संभावनाएं उज्ज्वल हुई हैं।

कुल मिलाकर, निकट अवधि की वृद्धि की गति में कुछ कमी आई है जबकि वैश्विक कारक प्रतिकूल हो रहे हैं। आगे देखते हुए, घरेलू वृद्धि चालकों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022-23 के लिए 7.8 प्रतिशत, क्यू1: 2022-23 में 17.2 प्रतिशत ; क्यू2 में 7.0 प्रतिशत ; क्यू3 में 4.3 प्रतिशत ; और क्यू4 में 4.5 प्रतिशत पर अनुमानित है।

मुद्रास्फीति

सीपीआई मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र हमारे अनुमानों के साथ निकट संरेखण में चला गया है। खासतौर पर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी से काफी राहत मिल रही है। खाद्यान्न उत्पादन में सुधार की संभावनाओं और सर्दियों की ताजा फसल की आवक पर सब्जियों की कीमतों में गिरावट की उम्मीद से आशावाद और बढ़ रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा मजबूत आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण दालों और खाद्य तेल की कीमतों में नरमी जारी रहने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना, हालांकि, मुद्रास्फीति संभावनाओं के लिए एक बड़ा अपसाइड जोखिम प्रस्तुत करता है। मुख्य मुद्रास्फीति सहनशीलता परीक्षण स्तरों पर उच्च बनी हुई है, हालांकि पिछले नवंबर में पेट्रोल और डीजल से संबंधित कर कटौती के निरंतर पारित होने से कुछ हद तक इनपुट लागत दबावों को कम करने में मदद मिलेगी। मांग में निरंतर कमी को देखते हुए बिक्री मूल्य पर इनपुट लागत दबावों का प्रसार कम रहा। इसके अलावा, जैसे-जैसे ओमिक्रोन जोखिम के घटने और आपूर्ति श्रृंखला के दबाव में कमी आती है, मुख्य मुद्रास्फीति में कुछ नरमी आ सकती है। शेष राशि पर, प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण जो बाद में नरम हो गया ति4 को 5.7 के साथ, 2021-22 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 5.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। विशेष रूप से, प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण जनवरी 2022 के लिए सीपीआई रीडिंग ऊपरी सहनशीलता बैंड के करीब जाने की उम्मीद है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून की धारणा पर, व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के

साथ, 2022-23 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत, 2022-23 के ति1 में 4.9 प्रतिशत; ति2 में 5.0 प्रतिशत; ति3 में 4.0 प्रतिशत और ति4 में 4.2 प्रतिशत पर अनुमानित है।

वर्तमान समय में, घरेलू मौद्रिक नीति का संचालन मुख्य रूप से उभरती मुद्रास्फीति और विकास की गतिकी के अनुरूप है, भले ही हम अनिश्चित वैश्विक विकास और भिन्न मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं के स्पिलओवर के प्रति सतर्क हैं। हमारी मौद्रिक नीति मध्यम अवधि में मूल्य स्थिरता के अपने प्राथमिक जनादेश द्वारा निर्देशित होती रहेगी, साथ ही एक मजबूत और निरंतर आर्थिक बहाली भी सुनिश्चित करेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे कार्यों को सुविचारित और अच्छी तरह से संदेशित किया जाएगा।

वित्तीय स्थिरता

एक मजबूत और अच्छी तरह से काम करने वाला वित्तीय क्षेत्र संवृद्धि और विकास की नींव को मजबूत करता है। रिजर्व बैंक ने चलनिधि की कमी को कम करने, बाजार में विश्वास बहाल करने और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में संक्रामक को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाकर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम बैंकिंग और गैर-बैंक वित्तीय दोनों क्षेत्रों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को भी मजबूत कर रहे हैं ताकि कमजोरियों की पहचान, आकलन और निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा सके।

इस प्रकार, महामारी से प्रेरित अस्थिरता के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है और अब जैसे ही बहाली जोर पकड़ेगी और निवेश गतिविधि तेज होगी ऋण मांगों को पूरा करने के लिए एक बेहतर स्थिति में है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का तुलन-पत्र पिछले वर्षों की तुलना में उच्च पूंजी पर्याप्तता, एनपीए में कमी, उच्च प्रावधानीकरण कवर और बेहतर लाभप्रदता के साथ अपेक्षाकृत मजबूत हैं।

हालांकि, हमें, बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों पर महामारी के प्रभाव के प्रति सतर्क रहना होगा जब विनियामक राहतों और समाधानों के प्रभाव पूरी तरह से काम करेंगे। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाएगा कि वे तेजी से गतिशील

और अनिश्चित आर्थिक परिस्थिति में लचीलापन बनाने के लिए अपने कॉर्पोरेट सुशासन और जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों को और मजबूत करें। उन्हें पूंजी वृद्धि और उपयुक्त बफर के निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखने की भी आवश्यकता है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

महामारी ने सदी का संकट दिया है, जिसमें स्वास्थ्य आघात एक व्यापक आर्थिक और वित्तीय झटके में बदल गया है। ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए। नतीजतन, उधार लेने की लागत दशकों में अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई और स्प्रेड सभी रेटिंग एजेंसियों में संकुचित हो गई। सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर के रिपोर्ट स्तर जारी किए गए। कॉर्पोरेट संस्थाएं लाभप्रदता में सुधार करते हुए और भविष्य के कैपेक्स के आय को बरकरार रखते हुए उच्च लागत वाले ऋण को मूल रूप से डिलीवरेज करने और उसे कम करने में सक्षम रही हैं। कुल मिलाकर, वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से कार्यरत रही और बहाली की प्रक्रिया को सहारा दिया है। हमारे आकलन में, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत कार्रवाइयों ने एक सहज और व्यवस्थित तरीके से वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं।

इन उद्देश्यों को निरंतर आधार पर प्राप्त करने के साथ, रिजर्व बैंक ने अपने निभावकारी रुख के समर्थन में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखते हुए, गतिशील आधार पर चलनिधि को पुनर्संतुलित करने की ओर रुख किया है। इस पुनर्संतुलन में दो-तरफा परिचालन शामिल हैं: पहला, मुख्य परिचालन के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी की ओर से एक रात्रिय (ओवरनाइट) स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो से चलनिधि को पुनर्संतुलित करना, जो फरवरी 2020 के संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित विभिन्न अवधियों की परिष्करण नीलामियों द्वारा समर्थित है; और दूसरा, अल्पकालिक चलनिधि बेमेल और कमी को पूरा करने के लिए 1-3 दिन की परिपक्वता की रेपो नीलामी आयोजित करना, उदाहरण के लिए जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह के दौरान उम्मीद से अधिक जीएसटी बहिर्वाह के हालिया मामले में। प्रभावी चलनिधि प्रबंधन की कुंजी 'समय' और एक सूक्ष्म और फुर्तीला दृष्टिकोण है जो

जिस तरीके से तरलता झुकती है उस तरीके से तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

आरबीआई के पुनर्संतुलन परिचालन के परिणामस्वरूप, अगस्त 2021 में पुनर्संतुलन शुरू होने के बाद से स्थायी दर रिवर्स रेपो के तहत दैनिक औसत अवशोषण में तेजी से कमी आई है। हालाँकि, इसी अवधि में कम होने के बावजूद समग्र प्रणाली चलनिधि, बड़े अधिशेष में बनी हुई है। ओवरनाइट विंडो से दीर्घावधि के लिए अधिशेष चलनिधि के माइग्रेशन को दर्शाते हुए, प्रभावी प्रतिवर्ती रेपो दर – स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो की भारत औसत दर और लंबी परिपक्वता के वीआरआरआर - अगस्त 2021 के अंत में 3.37 प्रतिशत से बढ़कर 4 फरवरी 2022 तक 3.87 प्रतिशत हो गई।

यह विदित है कि 6 फरवरी 2020 को संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को जारी करते समय, दैनिक स्थायी दर रेपो और एक रिपोर्टिंग पखवाड़े के भीतर चार 14-दिवसीय मियादी रेपो को वापस ले लिया गया था। महामारी और संबंधित वर्क फ्रॉम होम और सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल के मद्देनजर, एमएसएफ और स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो विंडो को सामान्य परिस्थितियों में केवल दिवसांत के बजाय पूरे दिन चालू किया गया था। चलनिधि प्रबंधन के इस निष्क्रिय तरीके ने महामारी की स्थिति में बेहतर काम किया ताकि बाजार की उभरती परिस्थितियों के अनुसार चलनिधि के पर्याप्त प्रावधान/अवशोषण को सुनिश्चित किया जा सके।

आरबीआई से चलनिधि की अल्पकालिक मांग सहित सामान्य स्थिति की प्रगतिशील वापसी के साथ, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक लचीला और दक्ष बनाने के लिए इसे बहाल करना तर्कसंगत है। तदनुसार, चार निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले, विभिन्न अवधियों के परिवर्तनीय दर रेपो परिचालन अब से नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव चक्र के भीतर विकसित चलनिधि और वित्तीय स्थितियों द्वारा आवश्यक होने पर आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, 14 दिनों की अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) चलनिधि की स्थिति के आधार पर मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण के रूप में काम करेंगे और सीआरआर रखरखाव चक्र के साथ मेल खाने के

लिए आयोजित किए जाएंगे। तीसरा, इन मुख्य परिचालनों को आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष परिचालन द्वारा समर्थित किया जाएगा। लंबी परिपक्वता की नीलामी भी आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी। चौथा, 1 मार्च 2022 से, स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ परिचालन सभी दिन केवल 17.30-23.59 घंटों के दौरान उपलब्ध होंगे, न कि 09.00-23.59 घंटों के दौरान, जैसा कि 30 मार्च 2020 को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए लागू किया गया था। बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे शेष राशि को स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो से वीआरआरआर नीलामियों में अंतरित करें और परिचालन सुविधा के लिए ई-कुबेर पोर्टल में स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एसआईएसओ) सुविधा का लाभ उठाएं।

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपये (आईएनआर) ने वैश्विक स्पिलओवर के बावजूद, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की तुलना में भी लचीलापन दिखाया है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बफर और चालू खाता घाटे (सीएडी) के मामूली स्तर ने भारत की बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को सहारा दिया है। 2021-22 की पहली छमाही में, सीएडी सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत था, जो वस्तुओं और सेवाओं के मजबूत निर्यात पर आश्रित था। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और घरेलू आर्थिक सुधार के अनुरूप गैर-तेल आयात में वृद्धि के कारण हाल के महीनों में माल व्यापार घाटा बढ़ गया है। हालाँकि, आगे बढ़ने की मजबूत संभावनाओं के साथ आईटी सेवाओं के नेतृत्व में सेवाओं के उत्साहजनक निर्यात के कारण 2021-22 के दौरान सीएडी के सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत से नीचे बने रहने की संभावना है। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह मजबूत बना हुआ है, जिनसे पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों के साथ, सीएडी के इस मामूली स्तर को सहजता से वित्त पोषित करने की उम्मीद है।

¹ बैंकों को अपने दिन के अंत में सीआरआर शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने अगस्त 2020 में एक वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एसआईएसओ) सुविधा प्रदान की है जिसके तहत बैंक एक विशिष्ट (या सीमा) राशि को पूर्व-निर्धारित करने में सक्षम हैं, जिसे वे दिन के अंत में बनाए रखना चाहते हैं। बैंकों द्वारा बनाए रखे गए किसी भी कमी या अतिरिक्त शेष राशि, एसआईएसओ सुविधा के तहत सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) या रिवर्स रेपो बोलियां, जैसा भी मामला हो, को स्वचालित रूप से ट्रिगर करेगा।

मौद्रिक नीति के भिन्न रुख, भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और लगातार आपूर्ति बाधाओं के कारण अत्यधिक अस्थिर और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं निरंतर आधार पर अस्थिर वैश्विक स्पिलओवर के प्रति संवेदनशील हैं। इस प्रकार, भले ही महामारी से उबरना अधूरा है, नीति निर्माताओं को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी ओर से, रिज़र्व बैंक इन स्पिलओवरों से घरेलू अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को अलग करता रहा है और करता रहेगा। इसके अलावा, जबकि आरबीआई सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, बाजार सहभागियों की वित्तीय स्थितियों के व्यवस्थित विकास और प्रतिफल वक्र में भी हिस्सेदारी होती है। यह उम्मीद की जाती है कि बाजार सहभागी जिम्मेदारी के साथ शामिल होंगे और सहकारी परिणामों में योगदान देंगे जो सभी को लाभान्वित होगा।

अतिरिक्त उपाय

हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर कुछ अतिरिक्त उपायों की भी आज घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और नियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपाय निम्नानुसार हैं:

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि सुविधाओं को बढ़ाना

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹50,000 करोड़ और ₹15,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि सुविधाओं की घोषणा मई और जून 2021 में महामारी की दूसरी लहर के दौरान की गई थी। बैंकों को दो योजनाओं के तहत उधार देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे। तीसरी लहर द्वारा लाई गई निरंतर अनिश्चितताओं के कारण, दोनों योजनाओं को 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक बढ़ाया जा रहा है।

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) - सीमाओं में वृद्धि

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना मार्च 2019 में सरकार और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा दीर्घकालिक निवेश की

सुविधा के लिए शुरू की गई थी। इस योजना की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। इसलिए, इस योजना के तहत निवेश की सीमा को 1 अप्रैल 2022 से वर्तमान में ₹1.5 लाख करोड़ से ₹1.0 लाख करोड़ तक बढ़ाकर ₹2.5 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। यह सरकारी प्रतिभूतियों सहित घरेलू ऋण बाजार के लिए पूंजी के अतिरिक्त स्रोतों तक पहुंच प्रदान करेगा।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा

सबसे पहले 2013 में जारी ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की समीक्षा की गई और सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए फरवरी 2021 में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए। प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, सीडीएस संबंधी अंतिम निदेश आज जारी किए जा रहे हैं। ये दिशानिर्देश क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार के विकास की सुविधा प्रदान करेंगे और भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहन बनाने में मदद करेंगे।

बैंकों को अपतटीय विदेशी मुद्रा निपटान - रुपया डेरिवेटिव बाजार में कारोबार करने की अनुमति

भारत में बैंकों को पहले से ही अनिवासियों को रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव जैसे ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (OIS) ऑफर करने की अनुमति दी गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत में बैंकों को गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ अपतटीय विदेशी मुद्रा निपटान- ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (FCS-OIS) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। यह तटवर्ती और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को कम करेगा, अधिक कुशल मूल्य खोज को सक्षम करेगा और भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और गहन करेगा।

ई-रूपी (यूपीआई) का उपयोग कर प्रीपेड डिजिटल वाउचर के अंतर्गत अधिकतम सीमा में वृद्धि

एनपीसीआई द्वारा विकसित ई-आरयूपीआई प्री-पेड डिजिटल वाउचर का शुभारंभ अगस्त 2021 में किया गया था। एकल उपयोग नकदी रहित भुगतान वाउचर की सीमा ₹10,000 है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ई-रूपी वाउचर की सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 प्रति वाउचर करने का प्रस्ताव है और ऐसे ई-रूपी वाउचर को एक से अधिक बार (जब तक वाउचर की राशि पूरी तरह से भुनाई नहीं

जाती है) उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इससे लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के वितरण में और अधिक आसानी होगी।

एमएसएमई प्राप्य वित्तपोषण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को सक्षम करना – टीआरडीडीएस निपटान के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को बढ़ाना

व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरडीडीएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। टीआरडीडीएस में लेन-देन राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली के माध्यम से निपटाए जाते हैं। हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और एमएसएमई की बढ़ती चलनिधि आवश्यकताओं के वित्तपोषण में आसानी को और बढ़ाने के लिए, टीआरडीडीएस से संबंधित निपटनों के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को मौजूदा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

आईटी आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश (एमडी) और सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धतियों पर मास्टर निदेश (एमडी)

महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं की व्यापक आउटसोर्सिंग, आरबीआई की विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ग्राहकों द्वारा डिजिटल चैनलों के बढ़ते उपयोग से, विनियमित संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और उन्हें समेकित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, हितधारकों और

जनता की टिप्पणियों के लिए दो मसौदा निदेश जारी किए जाएंगे: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आईटी आउटसोर्सिंग) निदेश, 2022; और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धति) निदेश, 2022।

निष्कर्ष

हम कोविड-19 के अगले म्यूटेशन के बारे में निश्चित ज्ञान के अभाव में नाइटियन अनिश्चितता² की दुनिया में रह रहे हैं। अर्थव्यवस्था के भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता वायरस के विकास पर इतनी निर्भर है कि एक रोग का निदान उतना ही अच्छा या उतना ही बुरा है जितना कि दूसरा है और अल्पकालिक भी। यदि पिछले दो वर्षों में वायरस के साथ रहने ने हमें कुछ सिखाया है, तो यह कि विनम्र रहना है, लेकिन अपने आत्म-विश्वास पर दृढ़ रहना है, कभी भी साहस और आशावाद नहीं खोना है। जैसा कि महान लता मंगेशकर ने - जिन्हें हमने हाल ही में खो दिया - उनकी अमर आवाज में गाया: “आज फिर जीने की तमन्ना है”। इस खूबसूरत गीत की अगली पंक्ति के पीछे की भावना के साथ, उन्होंने आशावाद का एक शाश्वत संदेश दिया है।

हम, रिज़र्व बैंक में, घरेलू वित्तीय प्रणाली में विश्वास और साहस की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे हैं क्योंकि हमने व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ मजबूत और सतत विकास की नींव का पुनर्निर्माण किया। अनिश्चितता के सागर में यह हमारा सहारा रहा है। हम चुनौतियों के बीच निरंतर प्रयास करने की महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित हैं: “संतुष्टि प्रयास में निहित है, पूर्ण प्रयास पूर्ण जीत है³।”

शुक्रिया। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

² अर्थशास्त्र में, नाइटियन अनिश्चितता कुछ संभावित घटना के बारे में किसी भी मात्रात्मक ज्ञान की कमी है, जोकि मात्रात्मक जोखिम के विपरीत है। यह अपूर्ण ज्ञान की स्वीकृति है जो भविष्य की घटनाओं को अनिवार्य रूप से अप्रत्याशित बनाती है। इस घटना का नाम शिकागो विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री, फ्रैंक नाइट (1885-1972) के नाम पर रखा गया है, जिसका मौलिक कार्य जोखिम, अनिश्चितता और लाभ 1921 में प्रकाशित हुआ था।

³ महात्मा गांधी का एकत्रित कार्य (सीडब्ल्यूएमजी), खंड 26, पी. 293